



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2008/श्रावण 21, 1930

No. 287]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2008/SRAVANA 21, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2008

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/07/2008-डीजीएडी,—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपरचात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपरचात् प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन जन.गण, चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा कोरिया आर.पी. (जिन्हें एतदपरचात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न (जिन्हें एतदपरचात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 3-7-2006 की अधिसूचना सं. 14/05/2005-डीजीएडी के तहत अपने अंतिम परिणाम अधिसूचित किए थे ।

और यतः संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 29-8-2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 85/2006-सीमाशुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद नायलॉन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पॉलीएमाइड यार्न के नाम से भी जाना जाता है । नायलॉन फिलामेंट यार्न ऑर्गेनिक मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से बना सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है । टेक्सटाइल अनुप्रयोगों में नायलॉन फिलामेंट यार्न का विस्तृत उपयोग होता है जिसमें साड़ी, डुपट्टा, रिब्सों के ड्रेस मैटेरियल/फैशन वियर, फैसी कैंजुअल निट वियर, स्टॉकिंग्स तथा स्टॉक्स, इंटीमेंट वियर तथा फाउंडेशन वियर, लॉजरी तथा नाइट वियर, ब्रीफ्स, पैटीज, स्लाप्स, बच्चों के परिधान, खेल परिधान तथा एक्टिव वियर, स्विम वियर तथा बीच वियर, आउटर वियर, चिंड वियर, फैशन संबंधी सामग्री, इलास्टिक टेप्स, शो/फुटवियर लाइनिंग्स, लेस/फैन्सी टेप्स, टाई/स्कार्फ्स, फेदर यार्न, रिबन्स/सैटिन रिबन्स आदि शामिल हैं ।

विचारधीन उत्पाद में सिलाई वाले धागे को छोड़कर सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 के भीतर वर्गीकरणीय नायलॉन अथवा पॉलीएमाइड्स के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न जैसे फ्लैट यार्न-टिविस्टिड और/अथवा अनटिविस्टिड, पूर्णतः ड्रॉन यार्न (एफडीवाई) स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), पूर्णतः ओरिएंटिड यार्न (एफओवाई), उच्च ओरिएंटिड यार्न (एचओवाई), आंशिक ओरिएंटिड यार्न (पीओवाई)/सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 के भीतर वर्गीकरणीय टेक्सचर्ड यार्न-टिविस्टिड तथा/अथवा अनटिविस्टिड, और रंजित यार्न, सिंगल, डबल, मल्टिपल, फोल्डेड अथवा केबल्ड शामिल हैं लेकिन नायलॉन अथवा अन्य पॉलीएमाइड्स के हाई टेनेसिटी यार्न शामिल नहीं हैं। उत्पाद में नायलॉन फिलामेंट यार्न अथवा पॉलीएमाइड यार्न के सभी प्रकार जैसे, फ्लैट/टेक्सचर्ड/टिविस्टिड/अनटिविस्टिड, ब्राइट/सेमी-डल/फुल-डल (अथवा उसके प्रकार), ग्रे/कलर्ड/रंजित (अथवा उसके प्रकार), सिंगल/डबल/मल्टिपल/फोल्डेड/केबल्ड (अथवा उसके प्रकार, चाहे वे आकार दिए अथवा अन्यथा हों, शामिल हैं लेकिन सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402.10 के अंतर्गत वर्गीकरणीय नायलॉन के हाई टेनेसिटी यार्न तथा सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402.10 के अंतर्गत वर्गीकरणीय फिशनेट यार्न शामिल नहीं हैं। तदनुसार सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 5402.10 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हाई टेनेसिटी नायलॉन फिलामेंट यार्न के सभी प्रकार वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर हैं। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से मौजूदा जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

3. जाँच शुरुआत

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 तथा उसके तहत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है। उपर्युक्त उपबंध के अनुसार संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों मै0 गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड, मै0 सेंचुरी इन्का लि0 तथा मै0 जेसीटी लिमिटेड ने मलेशिया के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा किए जाने की आवश्यकता जताते हुए एक याचिका दायर की है। पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बाद पाटन मार्जिन में हुई अत्यधिक वृद्धि के आधार पर समीक्षा की आवश्यकता जताई गई है। इसके अतिरिक्त मै0 हुआलॉन कॉर्पोरेशन (एम) एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया (निर्यातक को मिलने वाला व्यक्तिगत पाटनरोधी मार्जिन तथा पाटनरोधी शुल्क) ने भी यह सूचित करते हुए याचिका दर्ज की है कि किसी समझौते के मद्देनजर उनके सभी निर्यात रेक्रॉन (मलेशिया) एसडीएन, बीएचडी, के नाम पर किए जाएंगे और तदनुसार मै0 हुआलॉन पर लागू शुल्क मै0 रेक्रॉन पर लागू किए जाएँ। दिए गए प्रमाण तथा प्राप्त अनुरोध के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के उपबंधों तथा यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के अंतर्गत इस स्थिति में मलेशिया से आयातों के संबंध में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित होगा।

4. शामिल देश

मौजूदा जाँच में शामिल देश मलेशिया है।

5. समीक्षा के आधार

भारतीय उत्पादकों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मलेशिया से आयातों के संबंध में पाटन की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है जिसके कारण लागू पाटनरोधी उपाय की समीक्षा अपेक्षित है और उन्होंने प्राधिकारी से मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन के पुनर्निर्धारण हेतु समीक्षा का अनुरोध इस आधार पर किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारण किए जाने के बाद से पाटन मार्जिन बढ़ गया है। मौजूदा अवधि में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए यह दावा किया गया है कि हुआलॉन कॉर्पोरेशन से निर्यात सामान्य मूल्य से अत्यधिक कम कीमत पर हैं और पाटन मार्जिन पूर्व में निर्धारित मार्जिन से बहुत अधिक है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता जताने के लिए पर्याप्त सकारात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी को मै0 हुआलॉन कॉर्पोरेशन (एम) एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया (निर्यातक को मिलने वाला व्यक्तिगत पाटन मार्जिन तथा पाटनरोधी शुल्क) से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि किसी समझौते के मद्देनजर उनके सभी निर्यात रिकॉन (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. के नाम पर किए जाएंगे और तदनुसार मै0 हुआलॉन पर लागू शुल्क मै0 रिकॉन पर लागू किए जाएँ।

6. प्रक्रिया

आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना, जो बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाते हुए लागू उपाय की समीक्षा की आवश्यकता लक्षित करती है, को ध्यान में रखते हुए अब निर्दिष्ट प्राधिकारी का विचार है कि उपरोक्त नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 3.7.2006 की अधिसूचना सं0 14/5/2005 के अंतर्गत अधिसूचित अंतिम परिणामों तथा दिनांक 29.8.2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 85/2006 के तहत लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित है। समीक्षा में दिनांक 3.07.2006 की अधिसूचना सं0 14/5/2005 के सभी पहलू शामिल हैं।

7. जाँच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 (12 महीने) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 शामिल होंगे।

8. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उसके दूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार भारत में संबंधित समझे जाने वाले भारत के आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा सं० 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जाँच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

9. समय-सीमा

वर्तमान, समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्ष उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2008

(Mid-term Review)

Subject : Initiation of mid-term review regarding anti-dumping duty imposed on Imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from Malaysia.

No. 15/07/2008-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) notified its final findings vide Notification No. 14/5/2005-DGAD dated 03.07.2006 recommending definitive antidumping duty on import of Nylon Filament Yarn (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP.

And whereas definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 85/2006 dated 29.08.2006.

2. Product under consideration

The product under consideration in the present investigation is Synthetic Filament Yarn of Nylon also known as Polyamide Yarns. Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. Nylon filament yarn has vast applications in textiles applications, which includes saree, dupatta, women's dress material / fashion wear, fancy casual knit wear, stockings and socks, intimate wear and foundation wear, lingerie and night wear, briefs, panties, slips, kids wear, sports wear and active wear, swim wear and beach wear, outer wear, wind wear, fashion accessories, elastic tapes, show/footwear linings, laces/fancy tapes, tie/scarves, feather yarn, ribbons/satin ribbons, etc.

The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, other than sewing thread, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn - twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402, but excludes high tenacity yarn of nylon or other polyamides. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/textured/twisted/ untwisted, bright/semi-dull/ full-dull (or variants thereof), Grey/colored/ dyed (or variants thereof), single/ double/ multiple/ folded/ cabled (or variants thereof), whether or not sized, but excludes high tenacity yarn of nylon classifiable under customs sub-heading 5402.10 and fishnet yarn, classifiable under customs classification no. 5402.10. Accordingly, all types of high tenacity nylon filament yarn, classifiable under customs classification no. 5402.10 are beyond the scope of present investigations. The Customs classification, however, is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Initiation

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. In terms of the above provision the domestic producers of the subject goods M/s Gujarat State Fertilizers Company Limited, M/s Century Enka Limited & M/s JCT Limited have filed an application substantiating the need for mid term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Malaysia. The need for review has been established on the basis of significant increase in dumping margin after imposition of anti dumping duties. Further, M/s.Hualon Corporation (M) SDN.BHD.Malyaysia (the exporter attracting individual dumping margin and anti dumping duty) has also filed an application intimating that in view of an arrangement, all their exports will be in the name of Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. and accordingly duties applicable to M/s Hualon may be made applicable to M/s Recron. In view of the evidence provided and the request received, the

Designated Authority considers that the mid term review of the Anti Dumping Duty recommended in respect of imports from Malaysia would be appropriate at this stage under the provisions of rule 23 of AD Rules and Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended.

4. Countries Involved

The country involved in the present investigation is Malaysia.

5. Grounds for Review

The Indian producers in their application have claimed that the conditions of dumping have changed substantially with regard to imports from Malaysia requiring a review of the anti-dumping measure in force and have requested the Authority for the review for re-determination of dumping margin in respect of imports of subject goods from Malaysia on the grounds that dumping margin has increased since the determination by the Designated Authority. Considering the estimates of normal value and export price in the current period, it has been claimed that the exports from Hualon Corpn. are at prices significantly below the normal value and the margin of dumping is substantially higher than what was determined before. The applicants have provided sufficient positive evidence to prima facie establish the need for mid term review. The authority have also received a request from M/s.Hualon Corporation (M) SDN.BHD.Malyaysia (the exporter attracting individual dumping margin and anti dumping duty) intimating that in view of an arrangement, all their exports will be in the name of Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. and accordingly duties applicable to M/s Hualon may be made applicable to M/s Recron.

6. Procedure

Having regard to the information provided by the applicants indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated Authority now considers that a Mid Term Review of the Final Findings notified vide No. 14/5/2005-DGAD dated 03.07.2006 and the definitive Anti Dumping Duty imposed vide Customs Notification No. 85/2006 dated 29.08.2006 is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra. The review covers all aspects of Notification No. 14/5/2005-DGAD dated 03.07.2006.

7. Period of Investigation

The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2007 to 31st March, 2008 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2004-05, 2005-2006, 2006- 2007 and 2007-2008.

8. Submission of Information

The exporters in subject country, their government through their Embassy/ representative, the importers and users in India known to be concerned and the

domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

9. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of initiation of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

10. Inspection of Public File

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority